दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित: 28 फरवरी, 2024

उद्घोषित: 31 मई, 2024

<u>मू.वि.या.(वाणि) 104/2024 और अं.आ. 4567-4568/2024</u>

वर्चुअल वायर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
बी-1, न्यू आदर्श अपार्टमेंट,
सेक्टर-10, द्वारका,
नई दिल्ली-110075 .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री राकेश कुमार खन्ना, वरिष्ठ अधिवक्ता सह अधिवक्तागण सुश्री आभा आर शर्मा, सुश्री पूजा आनंद, डॉ विकास पहल और श्री राजा चटर्जी

बनाम

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन

2 रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001 ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अभिनव हंसारिया, अधिवक्ता

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय</u>

<u>न्या, नीना बंसल कृष्णा,</u>

1. यह याचिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (*इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित*) की धारा 34 के अधीन, याचिकाकर्ता की ओर से दायर की गई है, ताकि दिनांक 25.01.2024 के विवादित अंतरिम पंचाट को चुनौती दी जा सके, जिसमें अधिनियम, 1996 की धारा 16 के अधीन आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. यह प्रस्तुत किया गया है कि के विवादित अंतरिम पंचाट के माध्यम से, याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए, विद्वान् मध्यस्थ ने माध्यस्थम कार्यवाही जारी रखने का निर्णय लिया, जिससे याचिकाकर्ता को पूर्वाग्रहित किया गया है क्योंकि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है; यह आदेश विधि के विरुद्ध, विकृत है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

3. यह दावा किया गया है कि *अधिनियम की धारा 21*, अखंडनीय है और इसका अनुपालन अनिवार्य है, ताकि विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के अनुरोध की तिथि और जब यह अनुरोध दूसरी पक्ष द्वारा प्राप्त किया गया था, का निर्धारण किया जा सके। याचिकाकर्ता को कभी भी *अवलंबन* की कोई वैध सूचना नहीं दी गई थी, जैसा कि मुख्य याचिका में दायर दस्तावेजों के साथ-साथ दावेदार/प्रत्यर्थी द्वारा पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके साक्ष्य के शपथ-पत्रों से स्पष्ट है। विद्वान मध्यस्थ अधिनियम की धारा 21 के दायरे को बढ़ाकर कार्यवाही जारी नहीं रख सकता था।

4. इसके अतिरिक्त, *दिनांक 07-03-2007 के करार के खंड 8 और खंड 15* में प्रावधान है कि क्षेत्र के तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञों वाली एक निगरानी समिति परियोजना के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए इसकी निगरानी करेगी। यदि परियोजना की अवधि के दौरान, यह पाया गया कि इसे सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया जा सकता है, तो निगरानी समिति परियोजना को समय से पहले बंद करने का निर्णय ले सकती है जो सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी। *खंड 15* जिसमें मध्यस्थता प्रावधान किया गया था, में विशेष रूप से कहा गया है कि निगरानी समिति के तीन सदस्य एक माध्यस्थम न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करेंगे और बहुमत का निर्णय सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

5. परियोजना की निगरानी के लिए दिनांक 07-03-2007 के कार्यालय आदेश के *अधीन* तीन सदस्यों की निगरानी समिति गठित की गई थी। हालांकि, परियोजना के अंतिम चरण में, अंतिम किस्त के भुगतान में एक अस्पष्ट देरी हुई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा जारी नहीं किया गया था, लेकिन मनमाने ढंग से, अचानक और अनौपचारिक रूप से पूरी परियोजना को स्थगित कर दिया गया था। प्रत्यर्थी पत्र और अनुस्मारक के बावजूद राशि का भुगतान जारी करने में विफल रहा।

6. निगरानी समिति की बैठक 24.04.2012 को प्रत्यर्थी के कार्यालय/परिसर में आयोजित की गई थी, जिसके अनुसरण में याचिकाकर्ता को निर्देशों का पालन करने और याचिकाकर्ता द्वारा दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था। ऋण माफी और समापन के संबंध में निगरानी समिति का निर्णय करार के खंड 8 के अनुसार अंतिम और बाध्यकारी होना था।

7. प्रत्यर्थी ने बैठक के हस्ताक्षरित और निपटाए गए कार्यवृत्त के लगभग डेढ़ वर्ष बाद *दिनांक 20.12.2013 को एक कानूनी नोटिस* भेजा। प्रत्यर्थी ने दिनांक 21.02.2014 के पत्र के अधीन कथित विवादों को माध्यस्थम पैनल के रूप में निगरानी समिति की नियुक्ति करके करार के खंड 15 के अंतर्गत मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया।

8. प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी 2018 तक दावे का विवरण दर्ज करने में विफल रहा, हालांकि अपने स्वयं के निवेदन के अनुसार, इसने वर्ष 2014 में मध्यस्थता का अवलंबन किया था। माध्यस्थम पैनल 2014 तक 2018 तक अनिर्णायक रहा। इस प्रकार, प्रत्यर्थी ने अधिनियम की धारा 14(1)(क) और 15(2) के अधीन याचिका दायर की, जिसमें एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति द्वारा माध्यस्थम न्यायाधिकरण के प्रतिस्थापन की प्रार्थना की गई। उक्त आवेदन समय-सीमा से पूरी तरह से बाहर हो गया था और उक्त धाराओं के अधीन स्वीकार्य नहीं था। तथापि, इस न्यायालय ने याचिका की अनुमति दी और एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया।

9. याचिकाकर्ता ने उस आदेश के विरुद्ध एक *विशेष अनुमति याचिका* दायर की, जिसे इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया गया कि ऐसे सभी मुद्दों का निर्णय माध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा किया जा सकता है।

10. यह निवेदन किया गया है कि अधिनियम की धारा 16 के अधीन आवेदन को खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश, *एक अंतरिम पंचाट* है जिसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 34 के अधीन याचिका सुनवाई योग्य है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान मध्यस्थ का आदेश महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर विचार किए बिना दिया गया है और *स्पष्ट रूप से अवैध, विकृत और तर्कहीन है।* इसलिए, यह *प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। न्यायाधिकरण पक्षपाती था,* जो

स्पष्ट और प्रत्यक्ष है क्योंकि, दो बार समय लेकर दावे का विवरण दाखिल किया गया, जो कि सीमा अवधि से परे था, लेकिन विद्वान मध्यस्थ ने याचिकाकर्ता की आपत्ति को मामूली लागत लगाकर टाल दिया। प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित अंतरिम पंचाट इसलिए निरस्त किए जाने योग्य है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने दावों के समर्थन में, *भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड बनाम भद्रा उत्पाद,* (2018) 2 एससीसी 534; *बी एंड टी एजी बनाम रक्षा मंत्रालय,* एमएएनयू/एससी/0601/2023 और *श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्री नरेंद्र सिंह* एफएओ (सीओएम) 179/2021 और सीएम एपीपीएल 39706/2021 को आधार बनाया है।

12. **प्रत्यर्थी की ओर से** विद्वान अधिवक्ता ने कोई औपचारिक उत्तर दायर नहीं किया है, लेकिन आपत्ति उठाई है कि विवादित आदेश अंतरिम पंचाट नहीं है। यह केवल अधिनियम की धारा 16 के अधीन आवेदन को खारिज करने का आदेश है, जिसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 34 के अधीन याचिका विचारणीय नहीं है, जिसके लिए *दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य,* (2020) 15 एससीसी 706 को आधार बनाया गया है।

13. **प्रस्तुतियाँ सुनी गईं।**

14. धारा 34 के अंतर्गत याचिका की निर्वाह्यता के संबंध में *प्रारंभिक आपत्ति* उठाई गई है, जो अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध है।

15. *इफको लिमिटेड (उपर्युक्त)* मामले में, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम की धारा 16 *कॉम्पिटेंज- कॉम्पिटेंज* का सिद्धांत स्थापित करती है, अर्थात् माध्यस्थम न्यायाधिकरण स्वयं अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय ले सकता है। अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेते समय, यह तीन बातों को संदर्भित करता है: *(1) क्या एक वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद है; (2) क्या माध्यस्थम न्यायाधिकरण का उचित गठन हुआ है; और (3) मध्यस्थता को प्रस्तुत किए गए मामले मध्यस्थता समझौते के अनुसार होने चाहिए।* अधिकार क्षेत्र विभिन्न रंगों का एक कोट है, और इस शब्द का उपयोग जिस संदर्भ में किया गया है, उसके अनुसार इसका रंग बदल जाता है। अधिकार क्षेत्र को न्यायायलय के किसी कारण को सुनने और उसका निर्धारण करने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किसी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए; दूसरे शब्दों में, अधिकार क्षेत्र से तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके अधीन न्यायायलय उनके सामने प्रस्तुत किए गए मामलों का निर्णय लेती है या औपचारिक रूप से निर्णय के लिए प्रस्तुत मामलों का संज्ञान लेती है।

16. अधिनियम की धारा 16 माध्यस्थम न्यायाधिकरण की अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेने की क्षमता से संबंधित है। इसमें निम्नलिखित कहा गया है:

> ***"16. माध्यस्थम न्यायाधिकरण की अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेने की क्षमता।***
>
> *(1) माध्यस्थम न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय ले सकता है, जिसमें मध्यस्थता समझौते की अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय लेना शामिल है, और इसके लिए–*
>
> > *(क) एक अनुबंध का हिस्सा बनने वाला मध्यस्थता खंड अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र एक समझौते के रूप में माना जाएगा; और*
> >
> > *(ख) यदि माध्यस्थम न्यायाधिकरण यह निर्णय करता है कि अनुबंध शून्य और अमान्य है, तो इससे मध्यस्थता खंड की अमान्यता स्वतः नहीं मानी जाएगी।*
>
> *(2) यह दलील कि माध्यस्थम न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र नहीं है, बचाव के बयान की प्रस्तुति के समय से बाद नहीं उठाई जानी चाहिए; हालांकि, केवल इस आधार पर कि किसी पक्ष ने मध्यस्थ की नियुक्ति की है या नियुक्ति में भाग लिया है, उस पक्ष को इस दलील को उठाने से रोका नहीं जाएगा।*
>
> *(3) यह दलील कि माध्यस्थम न्यायाधिकरण अपनी प्राधिकरण सीमा से परे जा रहा है, उसी समय उठाई जायेगी जैसे ही वह मामला जो कथाकथित रूप से अपनी प्राधिकरण*

सीमा से बाहर है, मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान उठाया जाता है।

(4) माध्यस्थम न्यायाधिकरण उपखंड (2) या उपखंड (3) में उल्लिखित किसी भी मामले में, अगर वह देरी को न्यायसंगत मानता है, बाद की दलील को स्वीकार कर सकता है।

(5) माध्यस्थम न्यायाधिकरण उपखंड (2) या उपखंड (3) में उल्लिखित दलील पर निर्णय करेगा, और यदि वह दलील को अस्वीकार करने का निर्णय लेता है, तो वह मध्यस्थता प्रक्रिया को जारी रखेगा और मध्यस्थता पंचाट देगा।

(6) यदि माध्यस्थम पंचाट से कोई पक्ष पीड़ित हो, तो वह धारा 34 के अनुसार रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।"

17. धारा 16 का खंड 2 के अनुसार माध्यस्थम न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र की कमी के संबंध में आपत्ति बचाव के विवरण को प्रस्तुत करने के बाद नहीं उठाई जाएगी। किसी भी पक्ष, यहां तक कि वह पक्ष भी जिसने मध्यस्थ नियुक्त किया है, को मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने से नहीं रोका जा सकता है। जबकि खंड 2 क्षेत्राधिकार को चुनौती देने के लिए समय सीमा प्रदान करता है, खंड 3 में आगे यह प्रावधान है कि यह दलील कि अधिकरण अपने प्राधिकार के दायरे से बाहर है, को उसी समय उठाया जाएगा जैसे ही कथित रूप से अपने प्राधिकार के दायरे से बाहर जाने वाला मामला माध्यस्थम दलीलों के दौरान उठाया

जाता है। खंड 4 में माध्यस्थम अधिकरण को यह विवेकाधिकार दिया गया है कि यदि वह विलंब को न्यायोचित समझता है तो वह बाद में याचिका को स्वीकार कर सकता है।

18. उपधारा (ख) 5 यह प्रावधान करती है कि यदि माध्यस्थम न्यायाधिकरण धारा 2 या धारा 3 के अंतर्गत आवेदन को खारिज कर अपने अधिकार-क्षेत्र के पक्ष में निर्णय देता है, तो वह आगे माध्यस्थम कार्यवाही जारी रख सकता है और माध्यस्थम पंचाट पारित कर सकता है। ऐसा पंचाट, जिसे माध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया हो, धारा 34 के तहत चुनौती के योग्य बन जाता है, जैसा कि धारा 6 में उल्लेख किया गया है।

19. धारा 16 से यह स्पष्ट होता है कि माध्यस्थम न्यायाधिकरण के अधिकार-क्षेत्र को चुनौती देने वाले आवेदन के खारिज होने पर यह अनिवार्य है कि माध्यस्थम न्यायाधिकरण गुण-दोष के आधार पर आगे की सुनवाई करे। न्यायनिर्णय प्रक्रिया का अंतिम परिणाम पंचाट होता है, जो अधिनियम की धारा 34 के अधीन चुनौती के लिए पात्र है।

20. प्रश्न यह उठता है कि अधिनियम की धारा 16 के उपखंड (2) और (3) के अधीन आवेदन खारिज होने के मामले में किसी पक्ष के पास क्या उपाय उपलब्ध है।

21. अधिनियम की धारा 37 अपील योग्य आदेशों का प्रावधान करती है। धारा 37 की उपधारा (2) इस प्रकार है:

> *"(2) एक न्यायालय में अपील माध्यस्थम न्यायाधिकरण के आदेश से की जा सकती है:*
>
> *(क) **उस याचिका को स्वीकार करते हुए जिसका उल्लेख धारा 16 की उपधारा (2) या उपधारा (3) में किया गया है;** या*
>
> *(ख) धारा 17 के अंतर्गत अंतरिम उपाय प्रदान करने या प्रदान करने से इंकार करने पर।"*

22. यह विशेष रूप से प्रावधान करता है कि धारा 37 के अधीन अपील केवल तभी मान्य होगी जब धारा 16 (ख) और (ग) के तहत आवेदन स्वीकृत हो। यह स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 16 (ख) और (ग) के तहत आवेदन को खारिज करने के आदेश के विरुद्ध धारा 37 के अधीन अपील के उपाय को समाप्त कर देता है।

23. *एनटीपीसी लिमिटेड बनाम सीमेंस एटकेइंगसेलशाफ्ट* (2007) 4 एससीसी 451 के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने धारा 16 और 37 की व्याख्या करते हुए कहा कि धारा 37 की उपधारा 2 के तहत अपील तभी की जा सकती है जब धारा 16 (2) और (3) के तहत आवेदन को स्वीकार किया गया हो।

24. *एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड* (2005) 8 एससीसी 618 के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि उपधारा (5) के अंतर्गत न्यायाधिकरण पर यह दायित्व है कि वह याचिका पर निर्णय ले और यदि वह याचिका को अस्वीकार करता है, तो वह माध्यस्थम कार्यवाही जारी रखेगा और गुण-दोष के आधार पर अंततः पंचाट पारित करेगा। धारा 16 की उपधारा (6) यह और प्रावधान करती है कि ऐसा पक्ष जो माध्यस्थम पंचाट से पीड़ित हो, अधिनियम की धारा 34 के अधीन ऐसे माध्यस्थम पंचाट को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे पंचाट को चुनौती देते समय, एक पक्ष यह तर्क भी उठा सकता है कि न्यायाधिकरण को इसे पारित करने का अधिकार नहीं था या उसने अपनी अधिकारिता से अधिक कार्य किया। यह तभी होता है जब न्यायाधिकरण पंचाट पारित करता है। लेकिन, उस स्थिति में, जब न्यायाधिकरण अधिकार-क्षेत्र से संबंधित आपत्ति को खारिज करता है और अधिनियम की धारा 16 के तहत आवेदन को अस्वीकार करता है, तो कोई अपील प्रदान नहीं की जाती है और पक्ष को अंतिम पंचाट पारित होने की प्रतीक्षा करनी होती है, उस स्थिति में यह अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका में उठाया जा सकता है। हालांकि, ऐसी स्थिति में, जहां अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है और माध्यस्थम न्यायाधिकरण माध्यस्थम कार्यवाही को समाप्त

कर देता है, तो पीड़ित पक्ष सीधे अधिनियम की धारा 37(2) के अधीन अपील दायर कर सकता है।

25. *दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य (उपर्युक्त)* मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी तरह की टिप्पणियां की गई थीं, कि अधिनियम की धारा 34 के अधीन कोई अपील या याचिका अधिनियम की धारा 16 के अधीन आवेदन को खारिज करने के आदेश के विरुद्ध नहीं है।

26. आक्षेपित आदेश ने अधिनियम की धारा 16 के अधीन आवेदन को खारिज कर दिया है और गुण-दोष के आधार पर दावे का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ा है। इस तरह की बर्खास्तगी का आदेश अधिनियम की धारा 34 के अधीन चुनौती से परे है जैसा कि *पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड., (उपर्युक्त)* के मामले में आयोजित किया गया है।

27. धारा 16 के अंतर्गत आवेदन को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती देने में देरी करने का तर्क स्वाभाविक रूप से स्पष्ट है; मध्यस्थता अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक चरण में न्यायिक हस्तक्षेप को न्यूनतम करना था, ताकि मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के शीघ्र निपटान को प्रोत्साहित किया जा सके। यदि प्रत्येक आदेश को अपील योग्य बना दिया जाए, तो यह मध्यस्थता अधिनियम के उद्देश्य

को नष्ट कर देगा क्योंकि यह मुकदमेबाजी के समान बन जाएगा और इससे प्रक्रिया विलंबित हो जाएगी। अनुभव से यह पता चला है कि प्रत्येक आदेश के विरुद्ध न्यायालय जाने की प्रवृत्ति ने मध्यस्थता के माध्यम से मामलों के निपटान में अत्यधिक देरी उत्पन्न की है। इसी भावना के अनुरूप अधिनियम यह कल्पना करता है कि ऐसे आदेश, जैसे अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत आवेदन को खारिज करने वाले आदेश, जो मूलतः अंतरिम होते हैं, को अधिनियम की धारा 34 के अधीन याचिका में पंचाट के साथ चुनौती दी जा सकती है। अतः, वर्तमान याचिका अधिनियम की धारा 34 के अधीन विधि द्वारा वर्जित है; ऐसे आदेश को तब चुनौती दी जा सकती है जब यह अंतरिम/अंतिम पंचाट में परिणत हो।

28. महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका को इस आधार पर सही ठहराने की मांग की है कि इस तरह के आवेदन को खारिज करना अंतरिम पंचाट के समान है। ***इफको लिमिटेड (उपर्युक्त)*** के मामले में अंतरिम और अंतिम पंचाट के अंतर को स्पष्ट किया गया है।

29. यह देखा गया कि पूरे दावे को प्रभावित करने वाला प्रारंभिक मुद्दा, स्पष्ट रूप से एक अंतरिम पंचाट का विषय हो सकता है। *एक्समार बीवी बनाम नेशनल ईरानियन टैंकर को.* (1992) 1 लॉयड्स रिपोर्ट 169 के मामले में यह समझाया गया कि ऐसा पंचाट, जो किसी विशेष मुद्दे को अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए

पक्षों के अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु निपटाता है, अंतरिम पंचाट कहलाता है।

30. *सतसतवंत सिंह सोढी बनाम पंजाब राज्य* (1999) 3 एससीसी 487 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि अंतरिम पंचाट केवल अंतिम पंचाट की घोषणा होने तक प्रभावी रहने के लिए अभिप्रेत है, तो इसका प्रभाव अंतरिम पंचाट के रूप में होगा और अंतिम पंचाट के पारित होने के बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि अंतरिम पंचाट पक्षों के अधिकारों को अंतिम रूप से तय करने के लिए अभिप्रेत है, तो इसका प्रभाव एक पूर्ण पंचाट के रूप में होगा।

31. *मैकरमॉट इंटरनेशनल इंक बनाम बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड* (2006) 11 एससीसी 181 के मामले में, "आंशिक पंचाट की वैधता" शीर्षक के अंतर्गत, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 2(ग) के तहत पंचाट की परिभाषा में अंतरिम पंचाट शामिल है। धारा 31(6) भी अंतरिम पंचाट की परिकल्पना करता है। इस प्रावधान के अनुसार, अंतरिम पंचाट वह नहीं है जिसके संबंध में अंतिम पंचाट पारित किया जा सकता है, बल्कि यह उस विषय पर अंतिम पंचाट हो सकता है जो इसमें शामिल है, लेकिन एक अंतरिम चरण पर। यह भी देखा गया कि जब मध्यस्थ कुछ विवादों को प्रारंभिक स्तर पर मानने का निर्णय करता है और उन

दावों के संबंध में अंतिमता के साथ निष्कर्ष देता है, तो इसे अधिनियम की धारा 2(ग) के अंतर्गत सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए अंतिम पंचाट माना जाएगा।

32. उपर्युक्त निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि जिन मामलों को अंतरिम पंचाट में शामिल किया गया है, वे मुद्दे उस समय अंतिम पंचाट माने जाते हैं जब उनका अंतिम रूप से निर्णय किया जाता है, चाहे यह निर्णय माध्यस्थम कार्यवाही के मध्यवर्ती चरण में किया गया हो।

33. *इफको फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड* (उपर्युक्त) के मामले में, उपरोक्त निर्णयों में परिभाषित परीक्षा को लागू करते हुए, ___न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सीमावधि का मुद्दा जब तय कर लिया जाता है, तो उसमें अंतिमता होती है और यह एक अंतरिम पंचाट होता है, जिसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 34 के अधीन चुनौती दी जा सकती है।

34. *एनटीपीसी* (उपर्युक्त) (*नागरिक प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में*) के मामले में न्यायमूर्ति पी.के. बालासुब्रमण्यम ने एक अलग सहमति निर्णय में यह अवलोकन किया कि व्यापक अर्थ में दावे के गुण-दोष में जाने से इंकार करना अधिकारिता के क्षेत्र में हो सकता है। यहां तक कि सीमावधि के आधार पर दावे को खारिज करना भी न्यायालय की अधिकारिता को प्रभावित करता है। जब किसी दावे को सीमावधि के उल्लंघन के आधार पर खारिज कर दिया जाता है, तो यह एक प्रकार से वह

मामला बन जाता है जिसमें न्यायाधिकरण मामले के गुण-दोष पर अपने अधिकारिता का उपयोग करने से इंकार करता है। सीमावधि की याचिका पर पक्ष के पक्ष में निष्कर्ष देना न्यायालय की अधिकारिता को समाप्त कर सकता है, और इस प्रकार एक त्रुटिपूर्ण निर्णय को अधिकारिता के प्रश्न के साथ संबंधित माना जा सकता है, जो सीपीसी की धारा 115 के दायरे में आता है।

35. अतः, अधिनियम की धारा 16 के अधीन आवेदन के साधारण खारिज होने को, जो यह तय करता है कि मध्यस्थ न्यायनिर्णय को जारी रखने की अधिकारिता रखता है या नहीं, एक अंतरिम पंचाट नहीं कहा जा सकता। इसलिए, ***अधिनियम की धारा 34 के अधीन वर्तमान याचिका स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है।*** याचिकाकर्ता को इस आदेश को चुनौती देने के लिए, यदि आवश्यक हो, अंतिम पंचाट की प्रतीक्षा करनी होगी।

36. *विद्या द्रोल्या बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन,* (2021) 2 एससीसी 1 के मामले में यह संदर्भित करना प्रासंगिक होगा, जहां उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि धारा 11(6) के अधीन आवेदन पर विचार करने के चरण में दो मुख्य तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है: *क्या मध्यस्थता प्रावधान मौजूद है और क्या विवाद मध्यस्थीय हैं।* सीमावधि के मुद्दे को सामान्यतः विद्वान मध्यस्थ के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, सिवाय उन मामलों के जहां दावे स्पष्ट रूप से सीमावधि द्वारा अवरुद्ध दिखाई देते हैं।

37. अतः, अधिनियम की धारा 16 के उद्देश्य से, एकमात्र प्रासंगिक और महत्वपूर्ण कारक यह है कि क्या माध्यस्थम न्यायाधिकरण का गठन पक्षकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार किया गया था और क्या ऐसा न्यायाधिकरण का गठन सीमावधि के अधीन था।

38. अधिनियम की धारा 16 के अधीन आवेदन को खारिज करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई चुनौती का मुख्य आधार यह था कि मध्यस्थता का कोई उचित अवलंबन नहीं किया गया था क्योंकि अधिनियम की धारा 21 के अधीन अवलंबन की सूचना की तामील नहीं हुई थी और इसलिए, मध्यस्थ कार्यवाही शुरू करना कानूनी रूप से त्रुटीपूर्ण था।

39. विद्वान न्यायाधिकरण ने यह कहते हुए तर्कसंगत आदेश दिया है कि धारा 21 के अधीन सूचना की तामील हालांकि विवादित है, इसे दस्तावेजों की स्वीकार्यता/अस्वीकार्यता के समय स्वीकार किया गया था, जहां हस्ताक्षरों को स्वीकार किया गया था लेकिन नोटिस की सामग्री को अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए, विद्वान न्यायाधिकरण ने उचित रूप से निष्कर्ष निकाला है कि मध्यस्थ कार्यवाही शुरू करने से पहले नोटिस की तामील विधिवत स्वीकार कर ली गई है। यह भी देखा गया है कि दिनांक 20.12.2013 का उक्त *नोटिस*, धारा 21 के अनुसरण में है क्योंकि इसमें न केवल मध्यस्थता खंड का उल्लेख किया गया है बल्कि प्रत्यर्थी द्वारा उठाए जा रहे दावे की राशि भी बताई गई है। *यह नहीं*

कहा जा सकता है कि दावों को सीमावधि के उल्लंघन द्वारा अवरुद्ध किए जाने के संबंध में कोई निष्कर्ष दिया गया था। ये टिप्पणियां मुख्यतः मध्यस्थता की शुरुआत और इसके परिणामस्वरूप न्यायाधिकरण के गठन/नियुक्ति के संदर्भ में था, जो विधि के अनुरूप था।

40. एक बार जब न्यायाधिकरण का गठन हो जाता है, तो दावे को देर से दाखिल किए जाने या सीमावधि से बाहर होने की चुनौती न्यायनिर्णय और सुनवाई का विषय बन जाती है, और यह अधिनियम की धारा 16 के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं होती। इसके अलावा, दावों के सीमावधि के अंतर्गत होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है। दावों को सीमावधि द्वारा अवरुद्ध किए जाने का निर्धारण का चरण अभी आना बाकी है, और विवादित आदेश में, जो विद्वान् मध्यस्थ द्वारा माध्यस्थम कार्यवाही शुरू करने के अधिकारिता तक सीमित था, कोई गुण-दोष पर निष्कर्ष नहीं दिया गया है।

41. एक बार जब न्यायाधिकरण विधिवत रूप से गठित हो जाता है, तो अधिनियम की धारा 14 और 15 के अधीन आवेदन दाखिल करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। विद्वान् न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता के *इस तर्क को सही रूप से अस्वीकार* कर दिया कि प्रत्यर्थी द्वारा मध्यस्थ के प्रतिस्थापन के लिए पांच वर्षों के बाद धारा 14 और 15 के तहत आवेदन दाखिल करना सीमावधि द्वारा अवरुद्ध था।

42. याचिकाकर्ता का दूसरा तर्क यह था कि विद्वान् मध्यस्थ *पक्षपातपूर्ण* था, क्योंकि उन्होंने विद्वान् माध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा माध्यस्थम कार्यवाही शुरू करने के लगभग नौ वर्षों बाद *दावे का विवरण* प्रस्तुत करने की अनुमति दी। इस याचिका को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि माध्यस्थम कार्यवाही वर्ष 2014 में शुरू हुई थी और दावे को दाखिल करने की सीमावधि की गणना नोटिस की अवलंबन की तिथि, अर्थात् *20.12.2013*, से की जानी थी।

43. यह भी उल्लेखनीय है कि दावे के प्रस्तुत करने में देरी मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि हालांकि न्यायाधिकरण का गठन 2014 में किया गया था, यह कार्य नहीं कर सका और अंततः दिनांक 29.05.2018 को दिए गए नोटिस के माध्यम से माध्यस्थम न्यायाधिकरण के एक सदस्य ने नई दिल्ली में बैठकों के आयोजन में असुविधा व्यक्त की, जिससे अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत माध्यस्थम न्यायाधिकरण में बदलाव के लिए आवेदन की आवश्यकता पड़ी। वर्तमान विद्वान् मध्यस्थ की नियुक्ति 17.01.2023 को हुई और उन्होंने तत्पश्चात तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी। प्रत्यर्थी ने 04.04.2023 को दावा दाखिल किया और यहां तक कि दस्तावेजों की स्वीकार्यता/अस्वीकार्यता भी हो चुकी है और मामला साक्ष्य के चरण पर लंबित है; विद्वान् मध्यस्थ पर किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

44. यह भी देखा जा सकता है कि अप्र संशोधित मध्यस्थता अधिनियम की धारा 29-क में यह प्रावधान था कि मध्यस्थता कार्यवाही अठारह महीनों के भीतर संपन्न की जा सकती है। संशोधित धारा 29-क (23.10.2015 को संशोधित) ने याचिकाओं को पूरा करने के लिए छह महीने का समय दिया है, लेकिन यह समय सीमा अनिवार्य नहीं है; *बल्कि ये निर्देशात्मक हैं, जिन्हें विद्वान् मध्यस्थ के विवेक पर छोड़ दिया गया है।* यह धारा स्वयं मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार के विस्तार को मंजूरी देने का प्रावधान करती है ताकि न्यायनिर्णय को पूरा किया जा सके और यह विस्तार देने या मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने और पंचाट सुनाने के लिए किसी समयसीमा को निर्दिष्ट नहीं करती है।

45. एक बार जब न्यायाधिकरण अधिनियम के अनुसार अधिकारिता ग्रहण कर लेता है, तब वह याचिकाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा का विस्तार देने के अपने अधिकारिता के भीतर होता है; केवल इस कारण से कि याचिकाकर्ता को दो बार स्थगन दिया गया और वह भी लागत के अधीन, यह नहीं कहा जा सकता कि विद्वान् मध्यस्थ पक्षपातपूर्ण थीं। दावा प्रतिस्थापन मध्यस्थ की नियुक्ति के 90 दिनों के भीतर दायर किया गया था।

46. विवादित आदेश न तो विकृत है और न ही स्पष्ट रूप से अवैध, और यह भारतीय कानून की किसी भी मौलिक नीति का उल्लंघन नहीं करता। याचिकाकर्ता ने आदेश को चुनौती देने के आधार में केवल इन शब्दों का उपयोग किया है, बिना

यह समझाए कि आदेश विकृत कैसे है। यह स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया है कि अवलंबन की सूचना विधिवत प्रदान की गई थी और वह सीमावधि के भीतर थी। विवादित आदेश में कोई स्पष्ट अवैधता या विकृति नहीं है, और यह केवल अधिनियम की धारा 16 के अधीन आवेदन पर ही संबंधित है, जिसके *माध्यम* से विद्वान् मध्यस्थ की अधिकारिता को चुनौती खारिज कर दिया गया है। आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि धारा 16 के अधीन आवेदन का ऐसा खारिज होना न तो एक अंतरिम पंचाट है और न ही एक माध्यस्थम पंचाट, और अधिनियम की धारा 34 के अधीन कोई याचिका स्वीकार्य नहीं है।

47. याचिका को एतद द्वारा खारिज किया जाता है। लंबित आवेदनों का भी निपटान किया जाता है।

(नीना बंसल कृष्णा),
न्यायाधीश

मई 31, 2024/आरएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*